



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जून, 2010/28 ज्येष्ठ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जून, 2010

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-06-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 7) को

वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 11 जून, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

1994 का 4

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (13—ख) में "(राजस्व)" संशोधन। कोष्ठक और शब्द के स्थान पर "(अपील)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 4 का संशोधन।

"परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो वह किसी सभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं होगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में "तथा अक्टूबर मास के प्रथम रविवार" शब्दों के स्थान पर "के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्टूबर" शब्द रखे जाएंगे। धारा 5 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 7 का संशोधन।

“परन्तु कोई व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने, और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि उसने, खण्ड (छ) के अधीन वर्णित निरर्हता के सिवाए, धारा 122 की उपधारा (1) में वर्णित कोई भी निरर्हता उपगत की हो।”।

धारा 7-क
का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 7-क की उपधारा (5) में “15 प्रतिशत” और “एक तिहाई” अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः “50 प्रतिशत” और “आधा” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115 का
प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“115. बकाया की वसूली.—इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी अन्य रीति में वसूलीय होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, जल दर, किराया, फीस के बकाया के रूप में कोई रकम या पंचायत द्वारा दावा योग्य कोई अन्य धन, कलक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।”।

धारा 118 का
संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित किए जा सकेंगे और उसकी पहुंच पंचायतों की सुसंगत सूचना और अभिलेखों तक होगी।”।

धारा 138 का
संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) में “किसी पंचायत द्वारा” शब्दों के पश्चात् “या ग्राम सभा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल अधिनियम की धारा 144 में,—धारा 144 का
संशोधन ।

(क) शीर्षक में “, वस्तुएं तथा धन” चिन्ह और शब्दों के स्थान पर “तथा वस्तुएं” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में “या धन” शब्द जहां—जहां आते हैं, का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (3) में खण्ड (क) का लोप किया जाएगा ।

11. मूल अधिनियम की धारा 181 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—धारा 181 का
प्रतिस्थापन ।

“181. अपीलें.—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर और विहित रीति में,—

- (i) उप-मण्डल अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में उपायुक्त को;
- (ii) उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में मण्डलायुक्त को; और
- (iii) मण्डलायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में वित्तायुक्त (अपील) को;

अपील कर सकेगा और वह 90 दिन की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निपटारा करेगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।” ।

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ
(AMENDMENT) ACT, 2010**

(As Assented to by the Governor on 11th June, 2010)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,
1994 (4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh
in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title. **1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj
(Amendment) Act, 2010.

Amendment **2.** In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 4 of 1994
of Section (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), in clause (13-B), for the
2. brackets and word “(Revenue)”, the brackets and word “(Appeals)” shall
be substituted.

Amendment **3.** In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), after existing
of Section proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:—
4.

“Provided further that no person shall be entitled to be registered in
the list of voters of a Sabha area if he is already registered as a voter
in a Municipality.”.

Amendment **4.** In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), for the
of Section words “October and it”, the words and sign “on second October. It” shall be
5. substituted.

Amendment **5.** In section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the
of Section following proviso shall be inserted, namely:—
7.

“Provided that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the vigilance committee if he has incurred any of the disqualification mentioned in sub-section (1) of section 122, except the disqualification mentioned under clause (g).”.

6. In section 7-A of the principal Act, in sub-section (5), for the figures, sign and words “15%” and “one-third”, the figures, signs and words “50%” and “one-half” shall respectively be substituted. Amendment
of Section
7-A.

7. For section 115 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution
of Section
115.

“115. Recovery of arrears.— Any amount on account of arrears of any tax, water rate, rent, fee or any other money claimable by a Panchayat under this Act besides being recoverable in any other manner provided by this Act, may be recovered by the Collector, as arrear of land revenue:

Provided that the State Government may appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954).”.

8. In section 118 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment
of Section
118.

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the accounts of Panchayat may be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh and shall have access to relevant information and records of the Panchayats.”.

9. In section 138 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “by a Panchayat”, the words “or Gram Sabha” shall be inserted. Amendment
of Section
138.

10. In section 144 of the principal Act,— Amendment
of Section
144.

(a) in the heading, for the sign and words “,articles and money”, the words “and articles” shall be substituted.;

- (b) in sub-section (1), the words “or money” wherever these occur, shall be omitted.; and
- (c) in sub-section (3), clause (a) shall be omitted.

Substitution
of Section
181.

11. For section 181 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“181. Appeals.—Notwithstanding anything contained in this Act, any person aggrieved by an order made by the authorised officer under this chapter may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeal—

- (i) in case the order is passed by the Sub-Divisional Officer, to the Deputy Commissioner;
- (ii) in case the order is passed by the Deputy Commissioner, to the Divisional Commissioner; and
- (iii) in case the order is passed by the Divisional Commissioner, to the Financial Commissioner (Appeals);

and he shall hear and dispose of the appeal within period of 90 days and his decision shall be final.”.

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th June, 2010

No. AHY-B(1)-1/2008.—The Governor, Himachal Pradesh announce with deep sorrow the death of Dr. Vinod Sharma, Veterinary Officer, Sub Divisional Veterinary Hospital, Rohru, Distt. Shimla due to illness on 23rd May, 2010.

By order,
Sd/-
Secretary.

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th June, 2010

No. AHY-B(15)-13/97.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the voluntary retirement of Smt. Hem Lata Sharma, Superintendent Grade-I office of the Directorate of Animal Husbandry, Himachal Pradesh, Shimla-5 from Government service at her own request w.e.f. 14.08.2010 (AN).

By order,
Sd/-
Secretary

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the April, 2010

No. AHY-F(5)-10/2005—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to change the designation of the post of General Manager, HP State Cooperative Wool Procurement and Marketing Federation Ltd. to that of Chief Executive Officer in the same Pay Scale of Rs. 12000-

16350 (Revised Pay Scale of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7800) with immediate effect in the public interest, subject to the condition that the change of designation in no way, should become a basis of any up-gradation of scale of post.

1. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their UO No. Fin-IF-51388089/ 2010, dated 16.04.2010.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20 May, 2010

No. AHY-B(15)-13/97.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that following officers on their attaining the age of superannuation on the date(s) as shown against each, shall retire from Government service:—

Sr. No.	Name of officer/ Designation	Date of Birth	Date of retirement
1.	Dr. Anil Gupta, Dy. Director (AH/B) Kangra at Dharamsala, HP.	01.06.1953	31.5.2011 AN
2.	Dr. P.R. Vaidya, Dy. Director (AH/B) Mandi, HP.	4.02.1953	28.2.2011 AN
3.	Dr.D. C Azad, Asstt. Director (Project) O/O DD (AH/B) Kullu, HP.	2.05.1953	31.5.2011 AN
4.	Dr. Darshan Lal, Asstt. Director (AP), Chamba, HP.	05.04.1953	30.4.2011 AN
5.	Dr. Y.M. Azad, Asstt. Director (Project), O/O DD (AH/B), Dharamsala, HP.	7.03.1953	31.3.2011 AN
6.	Dr. Ram Lal Thakur, Asstt. Director SDVH, Kullu, HP	12. 02.1953	28.2.2011 AN

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2010

नस्ति सं रैव-डी (जी)7-9-2010.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज हरीश सीमटें लिमिटेड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के द्वारा उक्त उद्योग हेतु अधिग्रहित भूमि के फलस्वरूप मकानहीन होने वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय कलौनी हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत कम्पनी अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मुहाल जुगाहन व मुहाल चौक तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 में सीमेंट प्लांट में विस्थापितों के लिए कलौनी की स्थापना हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है । अतः एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया जाता है, उपरोक्त परियोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । जोकि उक्त उद्देश्य हेतु अधिग्रहण के उपरान्त राजस्व विभाग हि0 प्र0 को हस्तांतरित होगी ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल, हि0 प्र0 इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों के इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) सुन्दरनगर तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला मण्डी	तहसील सुन्दनगर	मौजा जुगाहण	खसरा न०	रक्बा		
				बीघा	वीस्वा	विश्वांसी
			340/2	12	2	5
			341	0	19	19
			342	2	0	1
			343	1	2	7
			344	1	2	7
			345	1	4	0
			346	1	8	11
			347/1	13	3	13
			348	1	14	8
			349	2	7	19
			350	9	0	1
			351	0	4	11
			352	0	4	0
			353	0	6	12
			354	0	11	11
			355	0	10	12
			356	0	3	17
			357	0	15	11
			358	0	2	15
			359	0	1	12
			360	0	1	12
			361	0	2	0
			362	0	10	1
			363	0	11	19
			364	0	13	11
			365	1	3	10
			367	1	19	5

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जून, 2010 / 28 ज्येष्ठ, 1932				1491
	374	5	0	15
	375	2	15	15
	377	8	12	6
	378	1	0	10
	379	0	6	14
	380	1	0	5
	381	0	9	17
	382	3	4	8
	383	1	9	7
	384	1	18	16
	385	0	9	9
	386	4	15	8
	501/388	8	4	0
	502/388	2	9	17
	503/388	2	12	11
	389	2	5	8
	390	2	9	10
	391	10	15	16
	392	2	5	0
	399	1	5	13
	400	2	9	3
	401	7	17	9
	402	4	0	15
	403	2	11	5
	404	1	1	0
	405	3	2	7
	406	1	13	8
	407	1	10	1
	408	0	15	0
	409	3	6	3
	410	9	15	16
किता	58	156 बीघा	7 बिस्वा	0 विश्वांसी

जिला मण्डी	तहसील सुन्दनगर	मौजा चौक	खसरा न०	रक्बा		
				बीघा	वीस्वा	विश्वांसी
			340/2	12	2	5
			85/2	0	14	8
			85/3	0	5	7
			81/1	0	0	3
			81/2	0	1	7
			79/2	0	1	12
			79/3	0	1	4
			79/4	0	12	15
			78/1	0	1	0
			78/2	0	2	5
			78/3	1	9	8
			67/1	0	1	18
			67/2	0	7	10
			67/3	4	0	3
			77/4	0	2	0
			77/2	0	8	6
			77/3	1	2	12
			76/1	1	3	15
			76/3	1	7	15
			76/2	0	4	12
			70/1	1	7	12
			70/3	1	6	4
			70/2	0	3	0
			69/1	1	14	13
			69/2	0	4	12
			69/3	1	0	15
किते			25	18 बिघा	4 बिस्वा	16 विश्वांसी

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

राजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 जून, 2010

संख्या: रैव0 1-4 (स्टाम्प)1/78-लूज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 03 अक्टूबर, 2009 को यथा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव 0 1-4 (स्टाम्प)-1/78 - लूज तारीख 29 सितम्बर, 2009 के क्रम में, उपरोक्त अधिसूचना तारीख 29 सितम्बर, 2009 की चौथी पंक्ति में आए "वित्तीय संस्थाओं" शब्दों के पश्चात् "और बैंकों" शब्द जोड़ने के आदेश देती है।

आदेश द्वारा
पी0 सी0 कपूर
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव।

[Authoritative English Text of the Notification No.Rev.1-4(Stamp)1/78-Loose dated 14th June, 2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th June, 2010

No. Rev.1-4 (Stamp)1/78-Loose.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) as applicable to the State of Himachal Pradesh and in continuation to this department notification no. Rev. 1-4(Stamp)-1/78-loose, dated 29th September, 2009, as published in the Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh, dated 3rd October, 2009, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to add the words "and Banks" after the words "Financial Institutions" appeared in the 5th line of the above notification dated 29th September, 2009.

By order
P. C. KAPOOR
F.C.-cum- Principal Secy.

**राजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)**

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 जून, 2010

संख्या: रैव0 1-4 (स्टाम्प)1/78-लूज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 03 अक्टूबर, 2009 को यथा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव 0 1-4 (स्टाम्प)-1/78-लूज तारीख 29 सितम्बर, 2009 के क्रम में, उपरोक्त अधिसूचना तारीख 29 सितम्बर, 2009 की दसवीं पंक्ति में आए “financial institutions” शब्दों के पश्चात् “and banks” शब्द जोड़ने के आदेश देती हैं।

आदेश द्वारा
(पी0 सी0 कपूर)
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ।

[Authoritative English Text of the Notification No.Rev.1-4(Stamp)1/78-Loose dated 14th June, 2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th June, 2010

No. Rev.1-4(Stamp)1/78-Loose.—In exercise of the powers conferred by Sections 78 & 79 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) as applicable to the State of Himachal Pradesh and in continuation to this department notification no. Rev. 1-4(Stamp)-1/78-loose, dated 29th September, 2009, as published in the Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh, dated 3rd October, 2009, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to add the

words “and Banks” after the words “Financial Institutions” appeared in the 10th line of the above notification dated 29th September, 2009.

By order,
P. C. KAPOOR
F.C. - cum- Principal Secy.

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A**

NOTIFICATION

Shimla-2 the 29th May, 2010

No. GAD-(F) 9-6/2009.— In continuation of this Department notification of even number dated 9th September, 2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare 26th June, 2010 as Gazetted Holiday in place of 28th June, 2010 on account of Sant Guru Kabir Jayanti (Prakat Diwas) to the employees working in all Government offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in Himachal Pradesh. This will not be a holiday under Section 25 of Negotiable Instrument Act. of 1881 and also to daily wage employees.

By order,
Asha Swarup
Chief Secretary.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 7th June, 2010

File No. PBW (B) F (7) 1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Technical Committee comprising of following officers to draft a proposal to frame strict quality

parameters for supply of Bitumen of required standard on competitive rates in Himachal Pradesh, with immediate effect, in public interest:—

- | | |
|--|----------|
| 1. The Engineer-in-Chief (QC&D), HP, PWD, U.S. Culb, Shimla-171001 | Chairman |
| 2. The Superintending Engineer (QC&D), HP, PWD, Shimla-171001 | Member |
| 3. The Store Purchase Officer, HP, PWD, Shimla-171002 | Member |
| 4. The Superintending Engineer, 4th Circle, HP, PWD, Shimla-171003 | Member |
| 5. The Executive Engineer (QC&D), HP, PWD Shimla-171001 | Member |

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.